House Building Advance to Central Government Employees

980. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to enhance the ceiling limit of House Building Advance in view of the rise in cost of materials used in house building; and

(b) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) Due to Budgetary constraints, it is not possible to earmark additional resources. Any enhancement in the quantum of House Building Advance would therefore lead to reduction in the number of beneficiaries. However, the Government are aware of the rise in the cost of building materials and labour. Hence the cost ceiling limit have been revised to 150 times the basic pay of the Government servant. This would enable him to obtain funds from other sources, if necessary by creation of second charge.

दिल्ली में पेयजल की मात्रा

981. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्लीवासियों को प्रति व्यक्ति कितना शुद्ध पेयजल उपलब्ध है ; और

(ख) दिल्ली में पेयजल की कमी को देखते हुये उसमें सुधार करने की सरकार की क्या योजना है और इस संबंध में क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि वे वितरण केन्द्र में औसतन 40 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से स्वच्छ जल सप्लाई कर रहे हैं ।

(ख) अलीपुर ब्लाक में लगभग 5 एम जी डी के उत्पादन के साथ दो रैनी कुंओं को इस वर्ष के अन्त तक चालू करने का प्रस्ताव है । 100 एम० जी०डी० क्षमता का एक जल शोधन संयंत्र हैदरपुर में स्थापित किया जा रहा है जो पूर्ण होने की अंतिम अवस्था में है परन्तु इसकी स्थापना कच्चे पानी के मिलने पर निर्भर करती है । इसके अतिरिक्त कमी को प्रतिपूर्ति और जल आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है:—

1. विभिन्न क्षेत्रों में पानी के वितरण को सुव्यवस्थित करना ।

2. विभिन्न क्षेत्रों में पानी के अतिरिक्त जलाशयों और बूस्टर पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण ।

3. अतिरिक्त शोधन संयंत्रों का निर्माण ।

4. पड़ोसी राज्यों से कच्चे पानी की उपलब्धता में वृद्धि करना ।

नयी आवास नीति

982. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **शहरी** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आवास की गंभीर समस्या को देखते हुये सरकार एक नयी आवास-नीति तैयार करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त नयी आवास-नीति को विभिन्न सरकारी स्तरों पर मंजूरी भी मिल चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस नीति को घोषित करने और इसे लागू करने के लिये कार्यवाही प्रारंभ करने में विलंब के क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) चूंकि राष्ट्रीय आवास नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे सभा पटल पर रख दिया गया है । राज्य सरकारों और संघ शासित राज्य के प्रशासनों तथा संबंधित केन्द्रीय सरकार के विभागों को नीति के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है ।

रोहिणी के फ्लैटों में घटिया सामग्री का प्रयोग

983. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई, 1992 को "टाइम्स आफ इंडिया" में "सब स्टैंडर्ड इन रोहिणी फ्लैटस" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी क्षेत्र में बनाये गये आवासीय-गृहों के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया गया है ;

(क) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Booking of Plots etc.

984. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of builders in the Capital are duping consumers and extorting huge sums for booking of plots etc.;

(b) whether Government propose to enact laws for compulsory registration of private builders;

(c) whether the mischievious activities of the builders would be curbed by enforcing some laws on them; and

(d) if so, the details of the steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Some news items appeared in this regard in the Press.

(b) to (d) A detailed proposal to introduce a Bill i.e. Delhi Apartment Regulation Act which would provide for compulsory registration of private builders, punitive measures for non-compliance of the terms and conditions entered into between the promoters and prospective buyers is under consideration of the Government.

Fire in Kanchanjunga Building

985. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the high rise building Kanchanjunga in Delhi was recently gutted in a fire;

(b) if so, what are the details thereof stating loss suffered as a consequence thereof;

(c) whether this building is one of the buildings which lacked fire fighting equipments;